

हंगामा है क्यों बरपा यानी कांग्रेस को हुआ क्या है?

राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद केंद्र में अराजकता का माहौल है। यह सब लोक सभा चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हुआ है, पर वास्तव में इसकी शुरुआत 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद ही हो गई थी। पार्टी को उम्मीद थी कि एक बार पराजय का क्रम थमेगा, तो फिर से सफलता मिलने लगेगी। उसकी सारी रणनीति राहुल को स्थापित करने के लिए सही समय के इंतजार पर केंद्रित थी। वह भी हो गया, पर संकट और गहरा गया। कांग्रेस ने वर्तमान संकट की जिम्मेदारी बीजेपी पर डाली है। कर्नाटक में वह तोड़फोड़ कर रही है। वह आपको खत्म करना चाहती है, तो आप क्या चाहते हैं? अपने सदस्यों को रोکنने की जिम्मेदारी आपकी है। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का इस दशा को प्राप्त करना उसके नेतृत्व के राजनीतिक कौशल पर सवालिया निशान लगाता है। बीजेपी आज ताकतवर हुई है। छह साल पहले तक तो आप बेहतर थे। आपकी दशा क्यों बिगड़ी



■ प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस

पार्टी के संकट को दो सप्ताहों पर देखा जा सकता है। राज्यों में उसके कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी केंद्र में अपने नेतृत्व का फैसला नहीं कर पा रही है। कर्नाटक में सांविधानिक संकट है, पर उसकी पृष्ठभूमि में कांग्रेस का भीतर असंतोष है। पार्टी छोड़कर भागने वाले ज्यादातर विधायक कांग्रेसी हैं। सामान्य विधायक नहीं, बल्कि बहुत सीनियर नेता हैं। कहना सही नहीं होगा कि पैसे के लिए पार्टी छोड़कर भागे हैं। ज्यादातर के पास काफी पैसा है। समझने की जरूरत है कि रोशन बेग जैसे कद्दावर नेताओं के मन में संशय पैदा क्यों हुआ? रामलिंगा रेड्डी जैसे वरिष्ठ नेता अपना रुख बदलते रहते हैं, पर इतना साफ है कि उनके मन में पार्टी नेतृत्व को लेकर कोई खिलश जरूर है। कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले विश्लेषकों को भी लगने लगा है कि पार्टी ने इच्छा-मूल्य का वरण कर लिया है।

केवल कर्नाटक की बात नहीं है। इसी गुरुवार को गुजरात में कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकौर और धवल सिंह जाला भाजपा में शामिल हो गए। दोनों ने राज्य सभा उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देने के बाद 5 जुलाई को ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ जेडीएस के विधायकों ने भी इस्तीफे दिए हैं, पर बड़ी संख्या कांग्रेसियों की है। इसके पहले तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक केसीआर की पार्टी टीआरएस में शामिल हो गए। ये विधायक दो महीने पहले ही जीत कर आए थे। गोवा में तो पूरी पार्टी भाजपा में चली गई। यह दल-बदल है, पर इसके पीछे के कारणों को भी समझने की जरूरत है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं के मन में असुरक्षा का भाव है।

संकट केंद्र में है

राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद केंद्र में अराजकता का माहौल है। यह सब लोक सभा चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हुआ है, पर वास्तव में इसकी शुरुआत 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद ही हो गई थी। पार्टी को उम्मीद थी कि एक बार पराजय का क्रम थमेगा, तो फिर से सफलता मिलने लगेगी। उसकी सारी रणनीति राहुल को स्थापित करने के लिए सही समय के इंतजार पर केंद्रित थी। वह भी हो गया, पर संकट और गहरा गया।

कांग्रेस ने वर्तमान संकट की जिम्मेदारी बीजेपी पर डाली है। कर्नाटक में वह तोड़फोड़ कर रही है। वह आपको खत्म करना चाहती है, तो आप क्या चाहते हैं? अपने सदस्यों को रोکنने की जिम्मेदारी आपकी है। देश की सबसे बड़ी

राष्ट्रीय पार्टी का इस दशा को प्राप्त करना उसके नेतृत्व के राजनीतिक कौशल पर सवालिया निशान लगाता है। बीजेपी आज ताकतवर हुई है। छह साल पहले तक तो आप बेहतर थे। आपकी दशा क्यों बिगड़ी?

उधर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व के बारे में फैसला टलता जा रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चंद्रयान की तरह टलती जा रही है। पार्टी फिलहाल कर्नाटक का संकट सुलझाना चाहती है। वह संकट इसलिए है, क्योंकि केंद्र में संकट है। कहा जा रहा है कि अब संसद का सत्र पूरा होने के बाद इस विषय पर फैसला होगा। उधर प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है।

१11२1२
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर राज्य में जब तक पार्टी संगठन का आधार मजबूत नहीं होगा, ऐसे बदलाव बहुत असर डालेंगे नहीं।

वरीयता क्या है?

वरीयताओं का सवाल भी है। तकलीफ पेट में हो, और इलाज कमर का चले तो बीमार का हाल क्या होगा? राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, पर वहां आज पार्टी बीजेपी, सपा और बसपा के बाद चौथे नम्बर पर है। पहली तीनों के बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरियां हैं। बेशक, प्रियंका के आगमन से जिला स्तर पर हलचल होगी, पर इस वक्त

ज्यादा बड़ा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। पिछले दो दिन से खबरें हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल नहीं, तो प्रियंका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें। राहुल पहले ही कह चुके हैं कि प्रियंका नहीं बनेंगी अध्यक्ष।

कोई गैरगांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो क्या प्रियंका उनके अधीन यूपी देखेंगी? पार्टी के भीतर पुराने और नई पीढ़ी के नेताओं के दो युट बतए जाते हैं। नये नेताओं को राहुल का समर्थन हासिल है। यदि नये नेताओं में से किसी को (मसलन मुकुल वासनिक, मिलिन्द देवड़ा, सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया को) अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या प्रियंका उनसे निर्देश लेंगी? और पुराने नेताओं (सुशील शिंदे, अशोक गहलोत, आनन्द शर्मा या मल्लिकार्जुन खड्गे जैसे) में से कोई अध्यक्ष बना तो क्या राहुल और शायद प्रियंका भी, उन्हें स्वीकार कर लेंगे?

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

कहां है

पूर्व-घोषित हत्या का रोजनामचा



■ राजेन्द्र शर्मा
वामपंथी चिंतक

‘रामदास उस दिन उदास था
अंत समय आ गया पास था
उसे बता, यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी।’

कर्नाटक

■ जनतंत्र की पूर्व-घोषित हत्या का जो मंजर हम पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा से देख रहे हैं, उसकी विडंबना को और सबसे बढ़कर उसमें जनता की लाचारी को, दिवंगत रघुवीर सहाय की चर्चित कविता, ‘रामदास’ की ये पंक्तियां बहुत ही बेधड़क तरीके से सामने रखती हैं। जिस जनता के नाम पर जनतंत्र का सारा तामझाम है, उसकी इससे बड़ी लाचारी क्या होगी कि, ‘सभी मौन थे, सभी निहत्थे/सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी।’

दुर्भाग्य से इस तरह ‘सभी निहत्थे’ कर दिए जाने में कर्नाटक के विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने भी कुछ न कुछ योग जरूर दिया है। अदालत के फैसले का व्यावहारिक अर्थ यही है कि कर्नाटक के सत्ताधारी जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के जिन विधायकों ने पाला बदल लिया है, उनके इस पाला-बदल पर दलबदल कानून की बंदिश लागू नहीं होगी। जिस पार्टी के टिकट पर चुनकर वे विधानसभा में पहुंचे हैं, उसकी सरकार गिरवाने के लिए विरोधियों का हथियार बनने के बावजूद, इसकी उन्हें इतनी कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी कि एक सीमित अवधि तक, उन्हें मंत्री पद से दूर रहना पड़े!

इसके बाद, एचडी कुमारस्वामी की सरकार पूर्व-घोषित हत्या से कैसे बच सकती थी। अलजता उसके जिहद होने से पहले के हाथ्यैर मारने ने, राज्यपाल जैसी संस्था के भी इस हत्या का सहयोगी होने को ही उजागर किया है। अचरज की बात यह नहीं है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, येदियुरप्पा के लिए अपने ऑपरेशन कमल-4.0 के कामयाब होने के बाद, इंतजार का एक-एक पल भारी हो रहा था। विश्वास मत पर मतदान की औपचारिकता, जितनी जल्दी पूरी होती, उनके लिए उतनी ही अच्छा था। विश्वास मत पर बहस लंबी खिंचती देखकर, उनके सगियों ने राज्यपाल का दरवाजा जो खटखटाया कि स्पीकर को निर्देश दें कि इस औपचारिकता में ज्यादा टाइम बर्बाद न करें।

गरिमा की रतीभर परवाह नहीं

और मोदी सरकार द्वारा राज्यपाल के पद पर बैठाए गए, गुजरात से निकले पूर्व-भाजपा नेता वजुभाई वाला ने, अपने पद की गरिमा की रतीभर परवाह न कर, राजनीतिक वफादारी का सवृत देते हुए, स्पीकर के लिए बाकायदा यह निर्देश भी जारी कर दिया कि, विश्वास मत रखे जाने के दिन दोपहर तक ही, उसका फैसला कर दें। और जब विधानसभा के स्पीकर ने इस अवैध निर्देश को अनुसूचक कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस अगले दिन जारी रहना तय हो गया, तो पहले तो इस आग्रह की खबरें फैलायी गयीं कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, धारा-356 लगाकर जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बाद में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर, उन्हें अगली दोपहर का डेढ़ बजे तक, बहुमत साबित करने का निर्देश दे दिया। बेशक, वाला के ऐसे राजनीतिक पक्षधरता दिखाने पर शायद ही किसी को

अचरज हुआ होगा। आखिरकार, चौदह महीने पहले विधानसभाई चुनाव के फौरन बाद, कांग्रेस और जेडीएस के स्पष्ट बहुमत के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बावजूद, वाला ने भाजपा नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ ही नहीं दिलवा दी थी, उन्हें बहुमत साबित करने के लिए दस दिन से ज्यादा का समय भी दे दिया था, ताकि विरोधी गठबंधन में तोड़-फोड़ कर के बहुमत जुगाड़ सके, जिसमें भाजपा और येदियुरप्पा वैसे भी माहिर हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने के लिए लंबा समय दिए जाने को अनुचित माना था और दो दिन में ही बहुमत की परीक्षा कराने का निर्देश जारी किया था। अंततः खरीद-फरोख की सारी कौशिशों के बावजूद, इतनी जल्दी खरीद-फरोख और तोड़-फोड़ के जरिए बहुमत न जुटा पाने के चलते, येदियुरप्पा को सबसे कम समय के



‘कांग्रेस-मुक्त’ भारत का नारा देने वाले नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव भाजपा ने, अपने इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में तुरंत-तुरंत कांग्रेसी से पूर्व-कांग्रेसी कराए गए उम्मीदवारों के साथ लड़ा और जीता था। इस विडंबना को रेखांकित करने वालों से यह प्रायः अनदेखा रह गया था कि यह रास्ता वास्तव में ‘विपक्ष-मुक्त’ भारत का है

मुख्यमंत्री का रिकार्ड बनाते हुए, इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल, खरीद-फरोख का यह खेल उसके बावजूद लगातार जारी रहा और अब 14 महीने बाद उस मुकाम पर पहुंचा है, जहां येदियुरप्पा अपने साथ बहुमत का समर्थन साबित करने के लिए उतावले हो रहे थे।

ऑपरेशन कमल-4.0

बहुमत का आंकड़ा ही नीचे खिसकाकर, विधानसभा में अल्पमत को बहुमत बनाने को इसी खेल का नाम ‘ऑपरेशन कमल’ है, जिसका आविष्कार पहली बार 2008 में येदियुरप्पा ने अपने अल्पमत को बहुमत में तब्दील करने के लिए किया था। इस ऑपरेशन के दो हिस्से हैं। विपक्षी सदस्यों से इस्तीफा दिलाकर बहुमत का आंकड़ा नीचे लाना। फिर उन्हें मंत्री बनाकर औपचारिक रूप से दलबदल कराना और भाजपा का उम्मीदवार बनवाकर जितवाना। यह खासतौर पर दलबदल कानून के 2004 के संशोधनों को धात बताने की कार्यनीति है, जो इस तरह दलबदल करने वालों को दलबदल की परिभाषा से और इसलिए उसे हतोत्साहित करने के लिए रखी गयी मामूली सजा से भी चतारी है। ऑपरेशन कमल-4.0 में, जो इस समय चल रहा है, इस खेल को और मारक बना दिया गया है। जहां पहले, एक-एक, दो-दो कर के विपक्षी विधायकों का शिकार किया जाता था, इस बार सत्तापक्ष के

एक साथ सवादूर्जन से ज्यादा विधायकों पर यह जाल डाला गया है।

जिनके लिए अब भी यह साबित किए जाने की जरूरत हो कि कर्नाटक में जो हो रहा था और हुआ है, सिर्फ कुमारस्वामी की सरकार का शिकार किए जाने तक या कर्नाटक तक ही सीमित मामला नहीं है, कर्नाटक के ताजतरीन ऑपरेशन कमल के सुखिंदों में रहते-रहते ही, गोवा में केंद्र व राज्य दोनों में सत्ता में बैठी भाजपा द्वारा इस ऑपरेशन के अगले चरण को भी आजमाया जा चुका था। अगला चरण, 2004 में संशोधित दलबदल कानून की गुंजाइशों के तहत, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक दल का ही, दो-तीनहाई बहुमत के बल पर, भाजपा में विलय कराने का था। बेशक, दलबदल कानून बनाने समय कम से कम यह नहीं सोचा गया था कि किसी पार्टी के संसदीय/विधायक दल के दो-तीनहाई बहुमत के ही खरीद लिए जाने की नौबत आ सकती है। बहरहाल, मोदी-2 में बाकायदा यह नौबत आ चुकी है। वास्तव में गोवा से भी पहले, यही दांव ऑंध्र प्रदेश में तेलंगू देशमू के राज्यसभा गुप पर आजमाया गया था और उसके चार राज्यसभा सदस्यों को भाजपा में मिला लिया गया था। गोवा और ऑंध्र प्रदेश के ये ऑपरेशन, वास्तव में दूसरी पार्टियों के लिए इसका संदेश हैं कि जो भाजपा का साथ नहीं देगा, उसके विधायकों/संसदीय यानी पार्टी को ही हाइजैक कर लिया जाएगा। हां! राज्यसभा में किसी भी तरह बहुमत जुगाड़ने की मुहिम में एक साथ, आवश्यकतामुरत सभी दांव आजमाए जा रहे हैं। यूपी में फिलहाल, पुराना ऑपरेशन कमल ही चल रहा है। चंद्रोखर पुत्र के पीछे-पीछे, सपा-बसपा के दो और राज्यसभा सदस्यों के भाजपागणमू गच्छामि करने की खबरें चल रही हैं।

‘विपक्ष मुक्त’ भारत

‘कांग्रेस-मुक्त’ भारत का नारा देने वाले नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव भाजपा ने, अपने इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में तुरंत-तुरंत कांग्रेसी से पूर्व-कांग्रेसी कराए गए उम्मीदवारों के साथ लड़ा और जीता था। इस विडंबना को रेखांकित करने वालों से यह प्रायः अनदेखा रह गया था कि यह रास्ता वास्तव में ‘विपक्ष-मुक्त’ भारत का है। मोदी-1 में इसका पहले अरुणाचल तथा उत्तराखंड में, थोक में दलबदल कराने के जरिए, सरकार कब्जाने की अदालत के हस्तक्षेप के चलते विफल कौशिशों में और आगे चलकर गोवा, मणिपुर, मिजोरम में, चुनावी अल्पमत को खरीद-फरोख से बहुमत में तब्दील करने की सफल कौशिशों में, विस्तार किया गया। मोदी-2 में इसी मुहिम को और आगे बढ़ते हुए ‘विपक्ष मुक्त’ भारत के लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया गया है। बेशक, राज्यसभा में बहुमत जुगाड़ना या कर्नाटक, बंगाल, केरल जैसी मुख्य विपक्षी सरकारों को उखाड़ना या भाजपा की गोवा जैसी डामग सरकारों को स्थिर करना, इस मुहिम की पहली प्राथमिकताएं हैं, लेकिन यह रास्ता साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों से मुक्त भारत का है।

नवउदारवाद के दौर में, जिस तरह एक ओर तो जीडीपी की संख्या के सिवा जनता के हित की नजर से सभी आर्थिक प्रयत्नों को राजनीति से बाहर किया गया है और दूसरी ओर राजनीति की मुख्यधारा में बड़े पैसे की तथा शहरी व ग्रामीण धनपतियों की बाढ़ आयी है, उसने राजनीतिक पार्टियों के बीच की विभाजक रेखाओं को पहले ही बहुत कमजोर कर दिया था। मोदी-2 में अब राजनीति से राजनीतिक पार्टियों यानी बची-खुची जनतांत्रिक राजनीति को भी बाहर करने की कौशिश की जा रही है। यह जनतंत्र की ही हत्या का रास्ता है।

मगर आप क्यों बिकने को हैं लालायित!

बादल सरोज

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक



कर्नाटक

■ लगी विधायकों की मंडी में अपने कुछ घोड़ों के बिचक कर भाजपा की हरी घास में पहुंच जाने के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में दहशत है। सुनते हैं कि अपने नवनविचारित संसद बेटे को दिल्ली ले जाकर नरेन्द्र मोदी के साथ फोटो उतरवाने सहित बाकी सब करने और इधर कुछ भी न करने के बावजूद मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉरपोरेट की थैलियां लिए गोवा से कर्नाटक होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते उठां के गिरोह से चौंकने हो गए हैं। अपने हर एक मंत्री पर जिम्मेदारता आये की है कि वह तीन तीन विधायकों पर नजर रखे। लगाता है कि मंत्रियों की निगरानी वे स्वयं करने वाले हैं।

मोदी और अमित शाह की भाजपा ने जरा से समय में भारत के संसदीय लोकतंत्र की चूल् हिलाकर रख दी हैं। खरीद फरोख, दल बदल, खुले आम रुपयों-बेशुमार रुपयों-के दम पर कर्नाटक से लेकर गोवा तक सरकारें खरीदने का जो खेल खेला जा रहा है, उसकी कोई मिसाल भारत के संसदीय लोकतंत्र को तो छोड़िए दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं मिलती। यह देश में एकदलीय शासन लाने भर तक का मामला नहीं है। यह 70 के दशक का आयागम गयामर के प्रहसन का भी फिर से मंच नहीं है। यह उससे कहीं आगे और गुणत्मक रूप से भिन्न और अलहदा मामला है। यह एकानुपालिकवर्तित राज कायम करने की दिशा में उठायी जा रहा एक और कदम है। साम, दाम, दंड, भेद और विच्छेद सारी तिकड़मों को आजमा कर देश को विपक्षविहीन करने की शांति चाल का हिस्सा है। लोकतंत्र की जगह, लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसा तानाशाही राज कायम करने का धक्करम है, जिसकी निकटतम मिसाल सिर्फ फासिस्ट हुकुमती में मिलती है। बहरहाल, इस पर विस्तार से बाद में कभी। फिलहाल मध्य प्रदेश और इस घटनाक्रम के दूसरे पहलू की बात करना प्रासंगिक होगा।

विधायकों की खरीद-फरोख

उस ऑफ हिंदुस्तान उगी करके विधायकों को खरीद रहे हैं- तो इसमें नई बात क्या है, उनका काम ही यह है! मगर आप क्यों टो जा रहे हैं? आपकी पूरी पूरी धान थोक के भाव क्यों बिकी जा रही है? जाहिर है कि यह सवाल कांग्रेस के आला कमान से लेकर उसके साधारण कार्यकर्ता तक को खुद से ही पूछना होगा! यह संघ-भाजपा की वैचारिक विजय से अधिक खासतौर से कांग्रेस और उसकी जैसी प्रजाति की वैचारिक पराजय

का परिणाम है। राजनीति जब किसी दर्शन या मूल्य के बजाय सिर्फ और केवल आर्थिक कमाई का जरिया बन जाती है, तब ऐसा ही होता है। कांग्रेस नाम की सवा सौ साल से ज्यादा पुरानी पार्टी बदलते-बदलते अब इतनी बदल चुकी है कि खुद ही खुद को पहचानने में असमर्थ हो चुकी है। गांधी पर हमले हों या नेहरू के खिलाफ कुत्सा का प्रचार, देश की आबादी को धर्म, जाति, उपजाति, गोत्र, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर खंड खंड करने की खुली ऐलानिया हरकतें हों या संवैधानिक संस्थाओं और खुद संविधान पर हमले हों, कांग्रेस में पता भी नहीं खड़कता। एक कांग्रेसी नहीं बोलता। बोलना तो बहुत दूर की बात है, अनेक तो कथित जनभावना के मम्माम में बचे-खुचे कपड़े भी उतार कर डुबकी मारने के लिए आतुर और तत्पर नजर आते हैं।

गांधी-नेहरू तो छोड़िए, अब हाथी पर बैठकर बेलछी जाने की हिम्मत दिखाने वाली प्रजाति भी नहीं बची है। कॉरपोरेट की लूट से कराह रहे देश के बारे में बोलेंगे नहीं। सांप्रदायिक फासीवाद की बढ़त के खिलाफ मुंह खोलने के बजाय कॉरपोरेट को खुश करने के लिए वामपंथ के खिलाफ चुनाव लड़ने वायनाड पहुंच जायें। बाबाओं की चरणारज सहजेंगे, मंत्रालय में घंटा बजायें। गुड़ खाएंगे और गुलगुलें से परहेज बतायेंगे। ऐसा कहावती भर में होता है, समाज या राजनीति में नहीं। जिस विचारभूतता की स्थिति में कांग्रेस है, उसमें उसका यही हाल होना है। उधर मोदी-अमित शाह की भाजपा सीबीआई से लेकर सारी एजेंसियों की राजनीतिक भयादोहन के लिए झोंके हुए है, और इधर मध्य प्रदेश में 15 साल के भाजपा राज के एक भी कुत्कर्म का आरोपी जेल तो दूर थाने तक नहीं पहुंचा। एक भी नीति नहीं उलटी गई, एक भी अफसर इधर से उधर नहीं हुआ। विश्वविद्यालयों से स्कूलों तक वही गिरोह है, जिसे हटाने का जनदेहि जनात न दिया था। दलालों के गमछों के रंग बदलने के सिवा कुछ नहीं बदला।

कुछ घट रहा, कुछ सिमट रहा कर्नाटक और गोवा दिख रहा है। मध्य प्रदेश दिखने की ओर बढ़ रहा है। मगर बहुत कुछ और है, जो घट रहा है सिमट रहा है, मगर उस अनुपात में दिख नहीं रहा। महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता भाजपा में समा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहा है। बाकी सब में भी अधिकांश बुलावे की इंतजार में बैठे हैं। जो अपने बुनियादी सरोकारों को त्याग देते हैं, उनके साथ यही होता है और यह बात सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही सच नहीं है। सुकून की बात बस इतनी है कि इतिहास जनता बनाती है, और जनता किसी के इंतजार की मोहातज नहीं होती। वह तूफानों को आंख दिखाकर, मंझारों को धात बनाती है, और मल्लाहों का भरोसा करने की बजाय तैर कर दरिया पार करती है।